भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 894

जिसका उत्तर 21.11.2019 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

894. श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री रवि किशनः

डॉ॰ रामशंकर कठेरियाः

श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस:

डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः

श्री हेमन्त पाटिलः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ई वी) एक सबसे बड़े बाजार बनने की अपार संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में इलेक्ट्रिक बसों के प्रचालन को प्रारंभ करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर व्यय की जाने वाली संभावित राशि कितनी है;

(ग) देश में राज्य-वार वर्तमान में प्रचालित इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमानित संख्या कितनी है और उक्त पहल के लिए सरकार द्वारा आवंटित निधि कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2021 तक सभी परंपरागत बसों को ईवी में परिवर्तित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ईवी अत्यधिक महंगे हैं और देश में इनकी बिक्री मात्रा कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार बसों हेतु बायो-गैस, सीएनजी, इथेनॉल और मिथेनॉल उपलब्ध कराने के लिए सेवा केन्द्रों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ईंधन के आयात को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं, जो पर्यावरणीय प्रदूषण को काफी हद तक कम कर सकता है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग): जी, हां। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए 01 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली 10,000 करोड़ रु. के परिव्यय से फेम इंडिया स्कीम चरण-II को वर्तमान में भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। यह स्कीम इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन राशि देकर और साथ ही आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करके इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। यह स्कीम लगभग 3545 करोड़ रु. की बजटीय

सहायता से लगभग 7000 ई-बसों की तैनाती का समर्थन करती है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ): जी, नहीं।

(ड.): फेम इंडिया स्कीम चरण-II इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन राशि देकर और साथ ही आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करके इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

(च): बसों के लिए उपलब्ध बायोगैस, सीएनजी, इथेनॉल और मेथनॉल बनाने के लिए खुदरा दुकानों की स्थापना किया जाना तेल विपणन कंपनियों और इस संबंध में अधिकृत/अधिकृत किए जाने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए वाणिज्यिक कार्यकलापों पर आधारित है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 08/11/2019 को अधिसूचना जारी की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख है कि पारंपरिक ईंधनों के अलावा अधिकृत संस्थाओं द्वारा उक्त खुदरा दुकान के प्रचालन के 3 वर्षों के भीतर प्रस्तावित खुदरा दुकानों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), जैव ईंधन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्थल आदि जैसे न्यूनतम इस नई पीढ़ी के वैक्लिपक ईंधनों के विपणन के लिए सुविधाएं स्थापित किया जाना अपेक्षित होता है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन आदि के यथा उपलब्ध विभिन्न अन्य सांविधिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने वाली संस्था के अध्यधीन है। यथा अनुप्रयोज्य सभी सांविधिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने वाली अन्य कंपनियों द्वारा नई पीढ़ी के अन्य परिवहन ईंधन की ब्रिकी के लिए उसी खुदरा दुकान के परिसरों का उपयोग करने के लिए किसी अधिकृत संस्था पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(छ): सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने, रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार, जैव ईंधन और नवीकरण को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता में सुधार और मांग प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही मंत्रालय ने संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बायोडीजल, फ्लेक्स ईंधन और इथेनॉल, मेथनॉल, एलएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस या तरलीकृत प्राकृतिक गैस इंजनों के साथ दोहरे ईंधन के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं। किए गए उपायों से देश की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता में कमी आने और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने की आशा है।

'इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा' के संबंध में श्री विनायक भाऊराव राऊत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री रवि किशन, डॉ. रामशंकर कठेरिया, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत और श्री हेमन्त पाटिलः द्वारा 21.11.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 894 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में इलेक्ट्रिक वाहन

क्र. सं.	**राज्य**	**कुल इलेक्ट्रिक वाहन**
1	अरुणाचल प्रदेश	13
2	असम	19,726
3	बिहार	23,256
4	छत्तीसगढ़	6,039
5	चंडीगढ़	700
6	दमन और दीव	60
7	दिल्ली	85,133
8	दादरा नगर हवेली	15
9	गोवा	403
10	गुजरात	4290
11	हिमाचल प्रदेश	171
12	हरियाणा	13,266
13	झारखंड	6001
14	जम्मू और कश्मीर	221
15	कर्नाटक	33,721
16	केरल	481
17	महाराष्ट्र	21,404
18	मेघालय	26
19	मणिपुर	268
20	मिजोरम	19
21	नगालैंड	39
22	ओडिशा	4255
23	पंजाब	2973
24	पुदुच्चेरी	966
25	राजस्थान	20,464
26	सिक्किम	23
27	तमिलनाडु	12,824
28	त्रिपुरा	916
29	उत्तराखंड	15,747
30	उत्तर प्रदेश	160,545
31	पश्चिम बंगाल	25,087
	कुल जोड़	**459,052**

नोट: 1 - दी गई गणना केंद्रीकृत वाहन 4 के अनुसार डिजिटाइज्ड वाहन रिकॉर्ड के लिए है।

नोट: 2 - आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं कराएं गए हैं क्योंकि ये केंद्रीकृत वाहन 4 में नहीं है।

नोट: 3 - केरल के आंकड़े अधूरे हैं क्योंकि पुराने आंकड़ों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है।

*****